भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2511

दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध

2511. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में दिखाई दे रहे तनाव के क्या कारण हैं, विशेष रूप से व्यापार वार्ता में प्रगति का अभाव और भारतीय पेशेवरों के लिए कार्य करने हेतु वीजा (वर्क वीज़ा) से जुड़ी निरंतर पाबंदियों और अनिश्चितता का ब्यौरा क्या है;

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक हितों और जन-केंद्रित संबंधों की सुरक्षा के लिए कौन से ठोस कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) शिखर सम्मेलन स्तर की घोषणाओं से इतर, भारत द्वारा विकास वित्त, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और ऋण राहत के संदर्भ में ग्लोबल साउथ को प्रदान किए गए वास्तविक लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्षों के बीच भारत अपने रणनीतिक एवं ऊर्जा हितों और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क से घ) हाल के दिनों में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में मुद्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए उच्च प्रशुल्क और अमेरिकी वीज़ा विनियमों में लागू किए गए परिवर्तन शामिल हैं, जिससे छात्रों और पेशेवरों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ा है।

इन घटनाक्रमों के बावजूद, दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और 2 फरवरी 2026 को, भारत और अमेरिका एक अंतरिम करार के लिए एक रूपरेखा पर सहमत हुए, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक प्रशुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच में वृद्धि होगी, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी तथा किसानों के हितों एवं ग्रामीण आजीविका की रक्षा होने की संभावना होगी।

वीज़ा के मामले में, दोनों पक्षकारों के हितधारक बातचीत कर रहे हैं और सरकार द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों से स्पष्टीकरण सबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया गया है, जिससे प्रभावित आवेदक श्रेणियों को बेहतर मार्गदर्शन मिला है।

भारत मजबूत अवसंरचना और सामुदायिक परियोजनाओं, वित्तीय एवं मानवीय सहायता, तथा छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्लोबल साउथ में मानव-केंद्रित विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ समिट्स के माध्यम से ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। एक स्थायी जी20 सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ का शामिल होना, वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों की आवाज़ को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत, ग्ल ोबल साउथ के लिए विकास संबंधी वित्त का एक बड़ा प्रदाता बना हुआ है और फिनटेक स्पेस सहित प्रौद्योगिकी परिनियोजन के लिए एक मॉडल है।

सरकार, भारत के राष्ट्रीय हितों और विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की लगातार निगरानी करती है। मिशन और केन्द्र नियमित रूप से परामर्शी जारी करते हैं, कोंसली सहायता प्रदान करते हैं और जहां आवश्यक हो वहां निकासी की सुविधा प्रदान करते है जिसमें 24×7 समर्थित हेल्पलाइन, मदद, सीपीग्राम्स और इ-माईग्रेट जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

ऊर्जा सुरक्षा, भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार आपूर्ति संबंधी स्रोतों के विविधीकरण, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, वैकल्पिक ऊर्जा के विस्तार और ऊर्जा परिवर्तन की उन्नति को शामिल करने वाली एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है, जबकि भागीदार देशों के साथ मिलकर वहन करने योग्य ऊर्जा को बिना रुकावट के पहुंच सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं।

*****